भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1132
05 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

पिंपरी चिंचवड़ को वित्तीय सहायता

†1132. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम को शहरी अवसंरचना में सुधार के लिए प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है और अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन और जल निकासी व्यवस्था के लिए दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;
(ख) प्रस्तावित पुणे रिंग रोड परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और शिरूर निर्वाचन क्षेत्र के लिए इसका क्या महत्व है;
(ग) शहर में भीड़भाड़ कम करने और निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(घ) सरकार का जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और शहरी विस्तार को रोकने के लिए पुणे के आसपास के अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहायता करने का क्या विचार है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) प्रश्न में उठाए गए मुद्दे मुख्यतः राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम को जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु गुणवत्ता सुधार और आवास के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), 15वाँ वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) और पीएमएवाई (शहरी) जैसी केंद्रीय और राज्य योजनाओं के तहत प्राप्त होती है। शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठों, प्रशिक्षण, डिजिटल निगरानी प्रणालियों और तृतीय-पक्ष गुणवत्ता आश्वासन के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने 122.82 किलोमीटर लंबी पुणे इनर रिंग रोड परियोजना को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस परियोजना की लागत 14,200 करोड़ रुपये है और इसका कार्यान्वयन पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) द्वारा किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण और डीपीआर तैयार करने का कार्य विभिन्न चरणों में है। इस परियोजना से शिरूर क्षेत्र से आने वाले यातायात के लिए भीड़भाड़ और प्रदूषण में कमी आने और कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भीड़भाड़ कम करने के उपायों में रिंग रोड, फ्लाईओवर, मिसिंग लिंक रोड का विकास, जंक्शन सुधार, मेट्रो और बीआरटीएस नेटवर्क का विस्तार, किफायती आवास परियोजनाएं और पर्यावरण सुधार कार्य शामिल हैं, जिनका उद्देश्य मोबिलिटी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

(घ) जनसंख्या वृद्धि का प्रबंधन करने और शहरी फैलाव को रोकने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि पीएमआरडीए शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करते हुए क्षेत्रीय योजना, आर्थिक विकास केंद्र, संरचना योजना, नगर नियोजन योजनाओं और कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय आयोजना का संचालन कर रहा है।

****